मुंद्रिका प्रसाद सिन्हा

बनाम

बिहार राज्य

20 सितंबर, 1979

[वी.आर. कृष्णा अय्यर और पी.एन. सिंघल, जे.जे.]

अधिवक्ता - सभी सरकारी मामलों के संचालन करने के लिए सरकारी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति – सरकार के पास सहायक सरकारी वकीलों को नियुक्त करने की और सरकारी प्लीडर से मामले वापस लेने की शक्ति है।

याचिकाकर्ता, जो एक सरकारी अधिवक्ता था, को सरकार द्वारा जिला न्यायालय में सभी दीवानी मामलों में इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया था। न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष बड़ी संख्या में सरकारी मामलों के लंबित होने पर विचार करते हुए सरकार ने याचिकाकर्ता के कार्यकाल के दौरान सरकारी अधिवक्ता के रूप में नौ सहायक सरकारी प्लीडर नियुक्त किए गए और उनसे सभी भूमि अधिग्रहण मामलों को एक सरकारी अधिवक्ता को सोंपने के लिए कहा। याचिकाकर्ता ने सरकार के निर्देशों का पालन करने से इंकार कर दिया और कहा कि वह स्वयं सभी मामलों का संचालन करेगा। लेकिन सरकार अपने रुख पर अडी

रही। सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली उसकी रिट याचिका खारिज को उच्च न्यायालय द्वारा ख़ारिज कर दिया गया।

अनुच्छेद 136 के तहत याचिका को ख़ारिज करते हुए -

अभिनिर्धारित किया 1. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(7) में निहित सरकारी वकील की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है, जिसे आदेश 21 नियम 4 और 8(सी) के साथ पढ़ने पर स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार के पास जितने सरकारी वकील हो सकते हैं। अपने मुकदमों का संचालन करना पसंद करता है। यह धारा एक सरकारी वकील पर दूसरों पर कोई एकमात्र नियंत्रण नहीं रखती है और सरकार किसी विशेष सरकारी वकील को विशेष मामलों का प्रभारी बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। सरकारी वकील और सहायक सरकारी वकील जिन्हें राज्य के प्रशासनिक नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया था, संहिता की धारा 2(7) में परिभाषा के अर्थ के तहत सरकारी वकील हैं। उनमें से प्रत्येक अन्य वकीलों को नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रतिनिधि पर नियंत्रण रख सकता है। [763 जी; 764 सी]

2. सरकारी वकीलों के संबंध में बिहार नियम, जो पूरी तरह से प्रशासनिक नुस्खे हैं और जो दिशानिर्देशों के रूप में कार्य करते हैं और जिन पर कोई कानूनी अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता है,

याचिकाकर्ता की मदद नहीं करते हैं। कार्य का आवंटन; या परस्पर नियंत्रण एक आंतरिक व्यवस्था है और सरकार के व्यवहार में कोई त्रुटि नहीं है। [764 एफ-जी]

3. जब राज्य के न्यायालयों में कई हजार मामले थे और न्यायाधिकरणों के समक्ष सैकड़ों मामले थे, तो यह सही था कि सरकार ने कई वकीलों की नियुक्ति न करके मामले के शीघ्र संचालन में कोई कमी नहीं की। यह समझ से परे है कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे किया होगा और भूमि अधिग्रहण के मामलों की इस भीड़ के मुवक्किल को कमोबेश एक ही समय में कई न्यायालयों में तैनात किया गया था। [765 डी-ई]

रामचंद्रन बनाम अलगिरिस्वामी, एआईआर 1961 मद्रास 450, अनुमोदित।

[1. 1957 में अखिल भारतीय कानून मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा विधि आयोग की सिफ़ारिशों को समाप्त करने के लिए विकसित की गई राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति के बावजूद, अभी भी ऐसी नीति से अनभिज्ञ न्यायालयों में सरकारी मामले का प्रसार हो रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य को समाधान पर जोर देने वाला एक आदर्श वादी बनना चाहिए। अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें न केवल मुकदमेबाजी नीति पर बल्कि वकीलों

की फीस नियमों पर भी दोबारा गौर करें, खासकर बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी में जिसमें भूमि अधिग्रहण मामलों में फीस तय करने में यथामूल्य गणना शामिल है। [762 बी; 763 सीए]

2. सरकारी नेतृत्व का राजनीतिकरण, जो एक सार्वजनिक कार्यालय है, कौशल की राजनीति द्वारा नियंत्रित और कानूनी एकाधिकार का आनंद ले रहे विकासशील समाज में एक क्षण का मुद्दा है। यह एक स्वस्थ परंपरा है कि सरकार जिला न्यायाधीश के परामर्श के बाद इन वकीलों की नियुक्ति करती है। हमारे संविधान के तहत सरकारें राजनीतिक या अन्य अनुचित विचारों पर कानून कार्यालयों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगी क्योंकि यह कार्रवाई की वैधता को प्रभावित कर सकता है और कानून के शासन को ही नष्ट कर सकता है। [765 सी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 6056/1979

पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 1618/79 में पारित निर्णय और आदेश के 12-7-1979 से उत्पन्न।

पी.गोविंदन नायर और एस. के. सिन्हा, याचिकाकर्ता की ओर से।

एल.एन. सिन्हा, अटॉर्नी जनरल, यू.पी. सिंह और आर.बी. महटन, प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

कृष्णा अय्यर, न्यायाधिपति.

एक सरकारी वकील, याचिकाकर्ता की एक असामान्य शिकायत, जिसे एक रिट याचिका में व्यक्त किया गया था, को उच्च न्यायालय द्वारा एक संक्षिप्त आदेश में कम कर दिया गया था, लेकिन इस सारांश संक्षिप्तता से निडर होकर याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में अपना मामला आगे बढ़ाया है। पूर्ण परिवेश में, उनका मामला एक सरकारी वकील की पेशेवर 'संपत्ति' के हिस्से के रूप में, आकर्षक भूमि अधिग्रहण मुकदमे सहित, पटना जिले के सभी सरकारी मामलों पर एकाधिकार का दावा है। मुकदमों की इस भारी भरकम रकम का संभावित नकद मूल्य उनके अनुसार लगभग एक लाख रुपये होने का अनुमान है और शायद यही रहस्य इस वकील की मुकदमेबाजी के पीछे छिपा है। हालाँकि, उनकी ओर से पेश हुए श्री गोविंदन नायर ने तर्क दिया कि न्यायालयों में सरकार के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उनके मुवक्किल का दावा लाभ कमाने के लिए कानूनी आवरण नहीं है, बल्कि राजनीतिक लोगों द्वारा सरकारी वकील के उच्च सार्वजनिक पद की अनुल्लंघनीयता की पुष्टि करना है। सचिवालय या 'थोड़ा संक्षिप्त अधिकार' का मुखौटा पहने पक्षपात करने वालों द्वारा, एक गहरा मुद्दा जिसमें बार की भी हिस्सेदारी है और बेंच को भी चिंतित होना चाहिए। हम पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं! उनका मानना है कि

न्याय के कुछ महत्वपूर्ण स्तरों पर, यदि बार प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो बेश बेंच लंगड़ा कर रह सकती है। हो सकता है कि उनके लगातार मुकदमेबाजी के लिए उनके पद के प्रति न्याय, न कि रुपयों का प्यार, को सम्मानजनक प्रेरणा माना गया हो।

तथ्यों का ताना-बाना, जिस पर कानून में शिकायत टिकी हुई है, पहले उसकी सराहना की जा सकती है। याचिकाकर्ता निश्चित रूप से पटना जिले का सरकारी वकील था, जो सभी सिविल मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत था। उनके कार्यकाल के दौरान नौ सहायक सरकारी वकील नियुक्त किए गए और उनमें से एक को भूमि अधिग्रहण मामलों के एक समूह का प्रभारी नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता से अनुरोध किया गया था कि वह उन विवरणों को नए नामांकित व्यक्ति को सौंप दे। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने किसी भी अन्य वादी की तरह, उसके अधीन किसी अन्य वकील को नियुक्त करने की सरकार की शक्ति को चुनौती दी और कभी भी उसे बाहर नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने सरकार को पत्र भी लिखा।

> "इसलिए, मैं इस मामले में किसी भी सहायक सरकारी वकील को काम करने की अनुमति देने के आपके निर्देश का पालन करने में असमर्थ हूं। मैं स्वयं इस मामले का संचालन करूंगा और मेरे पास इसके लिए पर्याप्त समय है।"

सरकार ने जवाब में लिखा कि भविष्य में उसे मामले नहीं दिए जायेंगे। आय की इस हानि और अपने एकाधिकार के विनाश से दुखी होकर वह एक रिट के सार्वभौमिक रामबाण उपाय के लिए उच्च न्यायालय में पहुंचा। अनुच्छेद 226 का रसायन विज्ञान कठोर द्वारा शासित है, और उच्च न्यायालय ने जादुई उपाय देने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने इस न्यायालय से विशेष अनुमति मांगी है लेकिन अनुच्छेद 136 की अपनी शर्तें और सीमाएं हैं। सार्वजनिक महत्व के कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के बिना, जिसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए या कम से कम जबड़े में दोष है जो स्पष्ट अन्याय से भरा है, न्याय के इस सदन के लिए कोई अन्य खुला समुद्र नहीं है। वह पासवर्ड यहां नहीं बताया गया है, पेशेवर शहादत के अभ्यास के बावजूद याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसे नुकसान हुआ है, और इसलिए हम दरवाजा बंद कर देते हैं लेकिन एक मौखिक आदेश के द्वारा क्योंकि वकील की दलीलें संभावित खतरे के साथ सरकारी वकालत के सार्वजनिक कार्यालय के लिए खतरे पर केंद्रित हैं न्याय प्रशासन. रहस्यवादी मूकता, चाहे कितनी भी सही हो, कभी-कभी गुमराह कर सकती है जब सादा भाषण अंततः चुप करा सकता है।

इस सरकारी वकील की कानूनी शिकायत की गंभीरता क्या है? उनकी आर्थिक शिकायत, भले ही वे इसे कितना भी छुपाएं, भूमि अधिग्रहण मामलों से शुल्क की संभावित हानि है, जिन्हें दूर कर दिया गया था। यह

'व्यावसायिक' पहलू एक नाखुश प्रलोभन है जिससे कानूनी पेशे को सावधान रहना चाहिए। पेशे के इर्द-गिर्द बयानबाजी और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, संक्षिप्त विवरण के लिए उत्सुकता है, क्योंकि वे फीस के रूप में एक लाख रुपये, न्यायालय में धोने के लिए एक साफ लिनेन प्राप्त करते हैं? संक्षेप में, बार का उन्मुखीकरण क्या है? 'लोगों के लिए तैयार या' आम जनता के खिलाफ साजिश?' सरकारी वकालत का राजनीतिकरण, जो एक सार्वजनिक कार्यालय है और वकील की फीस पर उचित सीमा की अनुपस्थिति में कानून कार्यालयों के लिए आकर्षक भूख, कौशल की राजनीति द्वारा नियंत्रित और कानूनी एकाधिकार का आनंद ले रहे विकासशील समाज में क्षणिक मुद्दे हैं।

देश के कई अन्य राज्यों की तरह बिहार राज्य में भी भारी मात्रा में मुकदमे हैं। सरकारी मुकदमेबाजी नीति किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण है यदि न्यायालयी कार्यवाही में अपनी भागीदारी बढ़ाने के बजाय कम करने के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाना है। यह खेदजनक है कि 1957 में अखिल भारतीय कानून मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति विकसित होने के बावजूद और जहां सरकार एक पक्ष है, वहां विवादों के निपटारे को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विधि आयोग की सिफारिशों के बावजूद वास्तविक व्यवहार में हम जो पाते हैं वह ऐसी किसी भी नीति से अनभिज्ञ अदालतों में सरकारी मामलों का प्रसार है।

दरअसल, इस देश में जहां सरकारी मुकदमेबाजी कुल मात्रा का एक बड़ा हिस्सा है, यह महत्वपूर्ण है कि राज्य को निपटान पर जोर देने वाला एक आदर्शवादी मुकदमाकर्ता होना चाहिए। केंद्रीय विधि आयोग ने केरल के एक फैसले को याद करते हुए 1973 में इस पहलू पर जोर दिया और आदेश 27 नियम 5 बी के रूप में पढ़े जाने वाले एक नए प्रावधान की सिफारिश की। आयोग ने देखा:

> 27.9. हमारा विचार है कि जिन मुकदमों में सरकार एक पक्ष है, उनमें समाधान के लिए सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देने वाला कुछ प्रावधान होना चाहिए।
>
> 27.10. उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित नियम को सम्मिलित करने की अनुशंसा करते हैं:-
>
> 5-बी (1) प्रत्येक मुकदमे या कार्यवाही में जिसमें सरकार एक पक्ष है या अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्य करने वाला एक सार्वजनिक अधिकारी एक पक्ष है, यह हर मामले में, पहले उदाहरण में न्यायालय का कर्तव्य होगा। मामले की परिस्थितियों की प्रकृति के अनुरूप लगातार ऐसा करना संभव है, ताकि मुकदमे की विषय-वस्तु के संबंध में किसी

समझौते पर पहुंचने में पक्षों की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सके।

(2) यदि, ऐसे किसी मुकदमे या कार्यवाही में, किसी भी स्तर पर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच समझौते की उचित संभावना है, तो न्यायालय कार्यवाही को उस अवधि के लिए स्थगित कर सकती है, जब वह उचित समझे, ताकि प्रयास संभव हो सके। इस तरह के समझौते को प्रभावी करने के लिए किया जाना है।

(3) उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति कार्यवाही स्थगित करने की न्यायालय की किसी भी अन्य शक्ति के अतिरिक्त है।"

इन व्यापक टिप्पणियों की प्रासंगिकता यह है कि परिहार्य मुकदमेबाजी फीस और अधिक शुल्क के माध्यम से धन रखती है यदि वे लड़े गए मामले हैं और यह एक वकील को, किसी भी अन्य होमो इकोनॉमिकस की तरह, सट्टेबाजी के आधार पर आय की गणना करने के लिए आकर्षित करता है, जैसा कि यह सरकारी वकील एक लाख रुपये की उम्मीद आधार करता है।

हमें अधीनस्थ न्यायालयों में सरकारी वकीलों की फीस के लिए बिहार सरकार के नियमों से अवगत कराया गया है। नियम 115 भूख और इसमें

शामिल कार्य की मात्रा या गुणवत्ता और न ही खर्च किए गए समय से कोई संबंध नहीं है। भूमि अधिग्रहण मामलों के लिए शुल्क तय करने में यथामूल्य गणना में वकीलों के लिए अनर्जित आय को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है। यहां याचिकाकर्ता संभवत: इसी प्रवृत्ति का शिकार हुआ है। समय आ गया है कि राज्य सरकारें न केवल मुकदमेबाजी नीति पर, बल्कि वकील की फीस नियमों (जैसे बिहार में नियम 115) पर भी दोबारा आर्थिक नजर डालें, खासकर बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी में, जिसमें यथामूल्य विशालता और यांत्रिक व्यावसायिकता शामिल है। यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र के स्रोतों से आय की सीमा भी पेशेवर प्रणाली के नैतिक स्तर को मजबूत करने में एक स्वस्थ योगदान हो सकती है। आख़िरकार, न्याय की कीमत कराहती जनता के लिए क़ानून के शासन का अंतिम पैमाना है। सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लाड़-प्यार नहीं करना चाहिए और इस तरह लागत प्रणाली को बढ़ाना नहीं चाहिए। यदि सरकारी नियमों में बिना परिश्रम आय की संभावना न दी गई होती तो शायद यह याचिका दायर ही न होती।

कानूनी रुख पर बारीकी से नजर डालने से मदद मिल सकती है। सरकारी वकील (याचिकाकर्ता) द्वारा व्यक्त किया गया स्पष्ट अन्याय यह है कि मामलों की इस भारी फसल से अपेक्षित 1 लाख रुपये की आधिकारिक आय, एक व्यवसायी द्वारा छीन ली जा रही थी। इस कथित अन्याय के

समर्थन में, उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(7) को लागू किया है जो इस प्रकार है:

> "2(7). 'सरकारी वकील' में सरकारी वकील पर इस संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से लगाए गए सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी और सरकारी वकील के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी वकील शामिल है।"

स्पष्ट रूप से, यह एक समावेशी परिभाषा है और, आदेश 27 नियम(4) और (8)बी(सी) के साथ पढ़ने पर, स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार के पास अपने मामलों को चलाने के लिए जितने चाहें उतने सरकारी वकील हो सकते हैं, यहां तक कि किसी भी मुवक्किल के पास, जिसके पास मुकदमों की सुनवाई के लिए बहुत सारी भीड़ है, मैं वकीलों की एक श्रृंखला नियुक्त करता हूं। सरकार एक सामान्य वादी से भी बदतर स्थिति में नहीं है और पेशे के भीतर एकाधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए बाध्य नहीं है। दरअसल, याचिकाकर्ता की सरकार के सभी मुकदमों में शामिल होने की इच्छा का मूल कारण यह है कि कानूनी पारिश्रमिक की उसकी नीति में कोई वितरणात्मक पूर्वाग्रह नहीं है और न ही सामाजिक रूप से शांत सीमा है। कुछ राज्य पहले ही ऐसी नीति अपना चुके हैं। वास्तव में, राज्य को अपने कानून अधिकारियों के संबंध में एक

नीति विकसित करनी चाहिए जो मामलों के निपटारे की सिफारिश करने की स्वतंत्रता प्रदान करे। यदि उन्हें लगता है कि ऐसा करना उचित है और वे वितरणात्मक न्याय को आगे बढ़ाते हैं जो वकील की अनुपस्थिति के कारण स्थगन की आवश्यकता को रोकता है और अंत में, निष्पादित सरकारी कार्य के लिए देय कुल शुल्क पर एक सीमा निर्धारित करता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(7) एक समावेशी परिभाषा होने के कारण किसी भी संख्या में सरकारी वकील की अनुमति देती है। यह एक सरकारी वकील पर दूसरे सरकारी वकील पर कोई एकमात्र नियंत्रण नहीं रखता है और सरकार किसी विशेष सरकारी वकील को 'विशेष मामलों का प्रभारी' बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उनमें से प्रत्येक एक सरकारी वकील है और अन्य वकीलों को नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्रतिनिधि पर नियंत्रण रख सकता है। इस दृष्टि से, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को दिए गए सारांश प्रेषण में कोई त्रुटि नहीं है, जिसका मुख्य गुण साहसिक नवीनता था।

हमें यह अवश्य कहना चाहिए कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अटॉर्नी जनरल ने एक वकील द्वारा संक्षेप में जानकारी मांगने या उससे चिपके रहने की आलोचना की थी और याचिकाकर्ता (एक पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश) के वकील ने याचिका के आर्थिक हिस्से

पर उचित रूप से लांचन लगाया और सरकारी वकील के उच्च पद के कानून के साथ उनके तर्कों को ख़ारिज कर दिया।

हम वकील द्वारा प्रस्तुत परिप्रेक्ष्य की पूरी तरह से सराहना करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर आएं, यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि यदि सरकार किसी सरकारी वकील द्वारा भरे गए सार्वजनिक पद का अपमान करने वाला कार्य करती है, तो गांधी की भूमि में जो पद पर आसीन होता है, वह पद का गरिमापूर्ण त्याग है, न कि 'रिट' मार्ग के माध्यम से खोए हुए पद की तलाश। इसके अलावा, कानूनी स्थिति स्पष्ट है. जैसा कि पहले बताया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(7) और आदेश 27 नियम (4) के अनुरूप सरकारी वकीलों का एक समूह पूरी तरह से स्वीकार्य है। न ही सरकारी वकील के संबंध में बिहार के नियम मदद करते हैं। वे पूरी तरह से प्रशासनिक नुस्खे हैं और दिशानिर्देश के रूप में काम करते हैं और उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं मिल सकता है, सिवाय इस तथ्य के कि वे एक से अधिक सरकारी वकील नियुक्त करने की सरकार की शक्ति का खंडन नहीं करते हैं। कार्य का आवंटन या परस्पर नियंत्रण एक आंतरिक व्यवस्था है और हमें उस व्यवहार में भी कोई त्रुटि नहीं दिखती है। जब मुकदमेबाजी की मात्रा इसकी मांग कर रही थी, तब अधिक सरकारी वकील उपलब्ध नहीं कराने से न्यायालय में डॉकेट्स अवरुद्ध हो

जाते और एक वकील को शीघ्र या कुशल निपटान के संदर्भ के बिना सभी संक्षेपों को किनारे करने में मदद मिलती।

जो भी हो, मुकदमेबाजी की प्रमुख धाराओं में से एक जिसमें सरकार खुद को उलझा हुआ पाती है, भूमि अधिग्रहण से जुड़ी है। राज्यों की विकासात्मक परियोजनाएँ, जो आवश्यक रूप से बड़ी होनी चाहिए, में बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण शामिल है। बिहार कोई अपवाद नहीं है. चूंकि मुआवजे के दावे सिविल अदालतों के समक्ष काफी संख्या में आते हैं, इसलिए राज्य को अपने अदालती मुकदमे पर शीघ्र ध्यान देने के लिए कई वकीलों को नियुक्त करना पड़ता है। राज्य ने इस आवश्यकता की सराहना करते हुए और अदालत को डॉकेट विस्फोट को खत्म करने में मदद करने के उद्देश्य से, मामले के प्रवाह के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए एक से अधिक सरकारी वकील नियुक्त किए। इस प्रकार, सरकारी वकील और सहायक सरकारी वकील राज्य के प्रशासनिक नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए थे। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(7) के तहत प्रत्येक व्यक्ति एक सरकारी वकील है।

यह जानकर ख़ुशी होती है कि बिहार सरकार जिला न्यायाधीश के परामर्श के बाद इन वकीलों की नियुक्ति करती है। यह राज्य के सर्वोत्तम हित में है कि उसे क्षमता की परवाह किए बिना राजनीतिक पक्षपात करने वालों की तलाश किए बिना सक्षम वकीलों को नियुक्त करना चाहिए।

सार्वजनिक कार्यालय और सरकारी नेतृत्व एक हैं - यदि सार्वजनिक कार्यालय में शुद्धता वांछित है, तो उन्हें टैमनी हॉल या उससे भी अधिक सूक्ष्म लूट प्रणाली के आगे नहीं झुकना चाहिए। आख़िरकार, राज्य से अपने मामले लड़ने और जीतने की उम्मीद की जाती है और सरासर संरक्षण सत्ता का दुरुपयोग है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका सरकारी वकीलों की पसंद के संबंध में जिला न्यायाधीश की सलाह पर कार्य करना है। जब पटना की अदालतों में कई हजार मामले थे और कई न्यायाधिकरणों के समक्ष सैकड़ों मामले थे, तो यह सही था कि सरकार ने अपनी ओर से कई वकील नियुक्त न करके मामलों के त्वरित संचालन का त्याग नहीं किया। एकल सरकारी वकील का आकर्षक अभ्यास। यह समझ से परे है कि यदि भूमि अधिग्रहण के मामलों की यह भीड़ एक ही समय में कई न्यायालयों या जेस में पोस्ट की गई होती तो उन्होंने अदालत और अपने मुवक्किल के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे किया होता। अधिवक्ताओं की सुविधा के अनुरूप स्थगन तब अभिशाप बन जाता है जब इसका उपयोग केवल वकील की आय बढ़ाने, पेशे के भीतर लोकतंत्रीकरण और वितरणात्मक न्याय का विरोध करने के लिए किया जाता है। ये सिद्धांत गिनती करने वालों को ख़राब अपील करते हैं, जो अफ़सोस की बात है।

याचिकाकर्ता के वकील के व्यापक प्रस्तुतिकरण की बात करें तो, हम निषिद्ध क्षेत्रों में भी राजनीति की घुसपैठ के हमारे युग में इसके महत्व को पहचानते हैं। एक सरकारी वकील किसी वादी के वकील से कहीं अधिक होता है। वह एक सार्वजनिक पद पर हैं। हम रामचन्द्रन बनाम अलागिरिस्वामी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ याद करते हैं और एक सरकारी वकील के कार्यालय के बारे में व्यक्त किए गए विचार को बिहार व्यवस्था में भी मोटे तौर पर सही मानते हैं।

> "... सरकारी वकील, मद्रास के कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्य हैं। इसके अलावा, जैसा कि पहले ही बताया गया है, जनता वास्तव में एक सरकारी वकील के कर्तव्यों के निर्वहन के तरीके से चिंतित है क्योंकि यदि वह अपने मामलों को खराब तरीके से संभालता है, तो अंततः उन्हें बिल का भुगतान करना होगा। राजस्थान का मामला मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखता है।
>
> (36) विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि सरकारी वकील, मद्रास केवल सरकार का एक एजेंट है, उसके कर्तव्य केवल सरकार के प्रति हैं जो उसके सिद्धांत हैं और जनता के प्रति

उसका कोई कर्तव्य नहीं है और इसी कारण से वह किसी सार्वजनिक पद का धारक नहीं होगा।

(37) इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना कठिन है। विद्वान महाधिवक्ता का तर्क कम अस्थिर हो सकता था यदि सरकारी वकील का कर्तव्य केवल उन अदालती मामलों का संचालन करना होता जिनमें सरकार एक पक्ष है। लेकिन, जैसा कि नियम हैं, उसे कई अन्य कर्तव्यों का पालन करना है। इसके अलावा, भले ही उसका एकमात्र कर्तव्य उन मामलों का संचालन करना है जिनमें सरकार को फंसाया गया है, फिर भी जैसा कि एक से अधिक बार समझाया गया है, जनता को इस बात में रुचि है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करता है ..... .

....

(90) मेरी स्पष्ट राय है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय के सरकारी वकील को राज्य द्वारा सरकारी खजाने से भुगतान किए गए पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है और उनके द्वारा नियत समय में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते

हुए उस कार्यालय का प्रयोग, जिनमें से अधिकांश स्वतंत्र और जिम्मेदार चरित्र के हैं, कार्यालय को अधिकार प्रच्छा कार्यवाही के दायरे में एक सार्वजनिक कार्यालय माना जाना चाहिए।

मेरा मानना है कि प्रश्न को निर्धारित करने के लिए सबसे उपयोगी परीक्षण वह है वह है जो (1851),17 क्यूबी 149 में एर्ले, जे. द्वारा निर्धारित किया है। तीन मानदंड हैं, कार्यालय का स्रोत, कार्यकाल और कर्तव्य। मैंने उस पाठ को लागू किया है और मेरी राय है कि यह निष्कर्ष कि कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है, अप्रतिरोध्य है।"

इस दृष्टि से, एक सरकारी वकील के बारे में आदेश देना अप्रिय है, लेकिन इस तरह के आचरण का कोई मतलब नहीं बनता है, हालांकि हमें एक चेतावनी देनी होगी कि हमारे संविधान के तहत सरकारें राजनीतिक या अन्य असंगत विचारों पर कानून कार्यालयों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगी क्योंकि इससे कानून की वैधता प्रभावित हो सकती है। कार्रवाई और कानून के शासन को ही नष्ट कर देना। आख़िरकार, एक सरकारी मुखिया और, एक तरह से, कानूनी पेशे के प्रत्येक सदस्य का लोगों के प्रति अधिक समर्पण होता है।

हम विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हैं लेकिन एक दुखद टैग के साथ, जो इस शहादत का संदेश है। व्यवसायों को 'प्रभावशाली, कुलीन, सुरक्षात्मक रंग' के साथ छिपी हुई साजिशों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जो एक ही समय में किसी को "नौकरी" या "व्यापार" के साथ हाथ मिलाए बिना काफी धन कमाने में सक्षम बनाता है। अठारहवीं शताब्दी के अंग्रेजी व्यवसायों के बारे में 'प्रोफेशन्स फॉर द पीपल' में तबाच्निक की टिप्पणियाँ ताज़ा लगती हैं:

> "कोई भी व्यक्ति व्यावसायिक परोपकारिता का परिधान पहनकर बैंड-बाजे की सहायता से व्यापार कर सकता है। आरंभ करने के लिए, कोई सीधे तौर पर आय प्राप्त किए बिना भी काम कर सकता है। जैसा कि पाठक बताते हैं:
>
> भुगतान का पूरा विषय. .....ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पेशेवर पुरुषों को गंभीर शर्मिंदगी का कारण बना दिया है, जिससे यह पता चलता है कि वे विस्तृत छिपाव, कल्पना और चालाकी का सहारा ले रहे हैं। मामले की जड़ इस भावना में निहित प्रतीत होती है कि प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक सज्जन द्वारा दूसरे को भुगतान करना उचित नहीं है, खासकर, यदि पैसा सीधे दिया जाता है। अतः बैरिस्टर की फीस का भुगतान वकील को करने की

व्यवस्था है, स्वयं बैरिस्टर को नहीं। इसलिए, यह परंपरा भी है कि कई पेशेवर व्यवहारों में शुल्क के मामले पर कभी भी खुलकर बात नहीं की जाती थी, जो बहुत सुविधाजनक हो सकता था, क्योंकि यह ग्राहक या रोगी को उस राशि के बारे में बहस करने से रोकता था जो उसका सलाहकार अंततः उचित मानदेय के रूप में इंगित कर सकता था। (1966) पृष्ठ 37).

सुस्थापित पेशे - कानून, चिकित्सा और पादरी-संपत्ति (या धारण करना जारी रखा) जैसे पदों पर रहे:-

अठारहवीं सदी के तीन 'उदार पेशे' वह केंद्र थे जिनके बारे में उन्नीसवीं सदी के पेशेवर वर्ग का निर्माण होना था। हमने देखा है कि वे शास्त्रीय शिक्षा के बंधन से एकजुट थे। उनके व्यापक और अपरिभाषित कार्यों में बहुत कुछ शामिल था जो बाद में नए, विशिष्ट व्यवसायों में बदल गया: अंततः, प्रत्येक ने, राज्य में स्थापित व्यवस्था के साथ अपनी स्थिति का अधिकांश हिस्सा प्राप्त किया ..... (1966, पृष्ठ 23)।"

समय आ गया है कि उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता की जांच की जाए, कीमत को नियंत्रित किया जाए, फर्श से छत तक, उन लोगों के प्रति प्रतिबद्धता लागू की जाए जो तीसरी दुनिया के ग्राहक हैं, और बुनियादी सामाजिक न्याय पर उन्मुख आंतरिक वितरणात्मक न्याय का अभ्यास किया जाए ताकि यह पेशा फल-फूल सके। अन्य व्यवसायों की देनदारियों से कानून द्वारा प्रतिरक्षित भौतिक संचय के सितारे को कॉल करने में पूरी तरह से बाधा डाले बिना। हम यह सुझाव नहीं देते हैं कि भारत में वकालत को अभी इंग्लैंड और अन्य जगहों की तरह एक राष्ट्रीय आयोग की आवश्यकता है, न ही हम अमेरिकी स्थिति से सहमत हैं जिस पर राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। हम उद्धरण देते हैं –

> "हम अधिक वकील हैं.... महान प्रभाव और प्रतिष्ठा वाले वकीलों ने नागरिक अधिकारों और आर्थिक न्याय के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया... उन्होंने अपने पेशे में भी नवाचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है.... एक पेशे के रूप में वकीलों ने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक सुधार दोनों का विरोध किया।"
>
> (राष्ट्रपति कार्टर, मई, 1978)

"हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वकीलों की भीड़, टिड्डियों की तरह भूखी भीड़, और बड़ी संख्या में न्यायाधीशों की ब्रिगेड होगी, जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी।"

(यू.एस. ओलिफ़ जस्टिस बर्गर)

कानून सुधार में वकील सुधार भी शामिल है, एक ऐसा मुद्दा जिसे याचिकाकर्ता ने अनजाने में उजागर कर दिया है। आख़िरकार, जैसा कि प्रो.कॉनेल कहते हैं-

"सामाजिक पूछताछ के समय में अपेक्षाकृत रूढ़िवादी संस्थानों की आलोचना शायद ही कोई नई घटना है।"

(ऑस्ट्रेलियन लॉ जर्नल, खंड 51, पृष्ठ 351)

यह लंबी न्यायिक यात्रा लघु उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करती है – याचिका ख़ारिज की जाती है।

पी.बी.आर.

(1) 1972 के.एल.टी 74 पेज 80
(2) देखें 54th कानून समिति की रिपोर्ट
(3) ए.आई.आर. 1961 मद्रास 450

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****